Minimum Support Prices for the Crop Year 1994-95

(Rs. per quintal)

Sl. No.	Commodity	Variety	Minimum Support Price
16.	Soyabean	Black	570
		Yellow	650
17.	Safflower	FAQ	780
18.	Toria	FAQ	800
19.	Tobacco (Rs. per Kg.)	VFC-F-2*	18.50
		1-2 Grade**	21.00
20.	SCopra (Milling)	FAQ	2500
	Ball	FAQ	2725

@ — These prices are linked to a basic recovery of 8.5% with preportionate premium for every 0.1% increase above that level.

* — Black Soil.

** — Light Soil.

$ — For Calendar year.

दिल्ली विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति

630. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति क्या है और विभिन्न स्त्रोतों के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रति वर्ष कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाती है तथा ऐसे प्रत्येक स्रोत का नाम क्या है;

(ख) क्या इस विश्वविद्यालय/संबंधित कालेजों के पास शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए धन उपलब्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और विश्वविद्यालय की इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार हैं; और

(घ) सरकार दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों में अध्ययनरत छात्रों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले घटकों के निवारण और उक्त समस्या के स्थायी समाधान के लिये क्या ठोस कदम उठाने का विचार कर रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित है । वि0अ0आ0 द्वारा भेजी गई सूचनानुसार वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 में क्रमशः 2853.05 लाख रुपये, 3109.78 लाख रू0 तथा 3301.96 लाख रुपये की राशि योजनेतर के अंतर्गत तथा 143.44 लाख रुपये, 23.00 लाख रुपये तथा 117.00 लाख रुपये, की राशि योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी गयी ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के सम्बद्ध कालेजों को इन वर्षो के दौरान 107.50 लाख रुपये, 148.98 लाख रु0 तथा 147.51 लाख रु0 की राशि योजना के अंतर्गत तथा 6729.32 लाख रुपये, 7154.80 लाख रु0 तथा 8032.10 लाख रुपये की राशि योजनेत्तर के अंतर्गत जारी की गई ।

(ख) सरकार को अभी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । शिक्षकों तथा विश्वविद्यालय/कालेजों के कर्मचारियों के वेतनों का भुगतान वि0अ0आ0 द्वारा जारी की गई योजनेतर राशि में से किया जाता है । जिसकी मात्रा में गत तीन वर्षो में वृद्धि हुई है, जैसा कि ऊपर भाग (क) में दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है ।

(ग) एवं (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये हुए अपर्याप्त अनुदान

631. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य कालेजों को अपर्याप्त अनुदान उपलब्ध कराये जाने के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है;

(ख) क्या यह सच है कि कालेजों में शिक्षकों के बहुत से पद इसलिये नहीं भरे जा रहे है क्योंकि शिक्षकों के वेतन के भुगतान के लिए धन उपलब्ध नहीं है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार आयोग द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कालेजों के लिए जारी किए गए योजनेतर अनुदानों की राशि में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई है । अतः इस धारणा का कोई आधार नहीं है कि निधियों की कमी के कारण इस विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध कालेजों में शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ है ।

(ख) और (ग) सरकार को शिक्षकों के वेतन के भुगतान के लिए निधियों की अनुपलब्धता के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

Short Supplies of Cod to Steel Sector

632. SHRI MOOL CHAND MEENA:
SHRI SANJAY DALMIA:
SHRI AJIT PK. JOGI:

Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether the required quantity of coal was not supplied to the steel producing units during 1994-95;

(b) if so, whether Government have ascertained the reason for the short supply of coal; and

(c) the steps Government propose to take to avoid recurrence of Such situation in future?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) There was a gap in supply of required quantity of coking coal from indigenous sources to the steel producing units in 1994-95.

(b) and (c) There is an overall shortage of availability of coking coal in the country. Besides, the difficulties in movement of coking coal from pithead to the plants on account of inadequate availability of wagons also affect supplies.

However, following steps have been taken to augment the supplies of coking coal;

(i) Close monitoring with Railways for day to day wagon supplies, uninterrupted Rail movement and placement of wagons for loading according to requirements.

(ii) Strict checks introduced to improve quality of washed coal produced.

(iii) Supply of Assam coal to SAIL and other plants.

(iv) Expediting completion of all modernisation works in the existing washeries.

(v) Close monitoring of various coking coal projects under implementation for augmenting the raw coking coal supplies.

(vi) Speedy commissioning of two coking coal washeries at Madhuband (2.50 MTPA) and Kedia (2.60 MTPA) under Bharat Coking Coal and Central Coalfields Limited respectively.

(vii) Early investment decision on construction of new coking coal washeries at Parej and Tapin. (3.75 MTPA).

viii) Setting up additional capacity to wash low volatile medium coking coal.

(ix) For further increasing washed coking coal availability to the steel plants, Coal India Limited has a programme to set up a coking coal washery in private sector under "Build-own-Operate" Scheme.